

प्रेषक

अरविन्द सिंह हयाकी
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में

मुख्य अभियन्ता स्तर-1,
लोक निर्माण विभाग
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2

देहरादून, दिनांक 24 अगस्त, 2007

विषय:- वित्तीय वर्ष 2007-08 में एन.पी.वी. भूमि प्रतिकर के भुगतान एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण आदि की प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र सं०- 2280/25 बजट(प्रतिकर)/2007-08 दिनांक 12.7.2007 के सन्दर्भ में वित्त अनुभाग-1 के पत्र सं० 599(1)/XXVII (1)/2007 दिनांक 26 मार्च 2007 तथा शासनादेश सं०-683/111-2/07-19(बजट)/2007 दिनांक 7 मई 2007 एवं सं०-1155/111(2)/07-19(बजट)/2007 दिनांक 25 मई 2007 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सड़क/भवन/पुल आदि हेतु भूमि के अधिग्रहण एवं प्रतिकर भुगतान हेतु आय-व्ययक में प्राविधानित ₹० 60.00 करोड़ (₹० साठ करोड़ मात्र) की धनराशि में से लेखानुदान 2007-08 के प्राविधान से अवमुक्त धनराशि ₹० 6.00 करोड़ (₹० छः करोड़) एवं पुनर्विनियोग द्वारा स्वीकृत ₹० 30.00 करोड़ (₹० तीस करोड़) को कम करते हुए अवशेष धनराशि ₹० 24.00 करोड़ (₹० चौबीस करोड़ मात्र) को व्यय हेतु आपके निर्वहन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- एन.पी.वी. एवं नृमिप्रतिकर का भुगतान एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण के भुगतान वर्षवार वरिष्ठता के आधार पर किया जायेगा। अर्थात् सबसे पुरानी देयता का भुगतान सबसे पहले तथा उसके बाद के वर्ष का उसके बाद तथा इसी वर्ष की सड़कों का सबसे अन्त में किया जायेगा, तथा वरिष्ठता के आधार पर जैसे-2 देयताओं का भुगतान किया जायेगा उसकी सूचना शासन को मासिक रूप से उपलब्ध कराई जायेगी। विभागाध्यक्ष के द्वारा उक्त देयों के भुगतान हेतु निर्वहन पर रखी जा रही धनराशि से परिपक्व दावों का भुगतान अपने स्तर से आवश्यकतानुसार किया जायेगा।

3- भूमि प्रतिकर भुगतान में मा० न्यायालयों एवं विधायिका में आश्वस्त किये गये प्रकरणों का भुगतान प्राथमिकता के आधार पर प्रथम वरीयता में किया जायेगा।

4- उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग एन.पी.वी. भुगतान हेतु वन विभाग को किया जाये।

5- जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित दरों पर विभाग द्वारा भुगतान किया जायेगा तथा कच की गई भूमि का शीघ्र विभाग के नाम हस्तान्तरण कर राजस्व अभिलेखों में दर्ज किया जायेगा।

6- उक्त धनराशि को व्यय करने से पूर्व बजट मैन्युअल, वित्तीय हस्तापुस्तिका के नियमों का या अन्य सुसंगत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा, तथा व्यय करने से पूर्व सहम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

7- स्वीकृत धनराशि का आहरण साख सीमा के माध्यम से आवश्यकतानुसार किया जायेगा।

8- स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.3.2008 तक पूर्ण उपयोग करके वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

9- यदि धनराशि स्वीकृत करने के बाद भी पूर्व के वर्षों की देयता रहती है और धनराशि शासन को समर्पित की जाती है तो इस हेतु उत्तरदायित्व का निर्धारण किया जायेगा। अतः स्वीकृत की जा रही धनराशि का समयबद्ध रूप से उपयोग व दायित्व विभागाध्यक्ष का ही होगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय साख परिधाय के अधीन, स्थापित नियमों एवं प्रक्रिया के अधीन ही सुनिश्चित किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया

Chud

जायेगा कि सभी परिपक्व रखे प्रस्ताव-2 की दरिद्रता के अनुसार तत्काल भुगतान सुनिश्चित करके इसका मासिक व्यय विवरण भी शासन को उपलब्ध कराया जाय।

10- इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2007-2008 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-22 लेखाशीर्षक-5054 सड़कों तथा सतुओं पर पूँजीगत परियोजना-04-जिला तथा अन्य सड़कों-आयोजनागत- 800-अन्य व्यय-05 सड़क/भवन/पुल आदि हेतु भूनि अधिग्रहण-00-24 वृहत्त निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

11- यह आदेश वित्त विभाग के अ.शा. सं०- 316/XXVII(2)/07, दिनांक, 22 अगस्त, 2007 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अरविन्द सिंह हयांकी)
अपर सचिव।

संख्या-2003 (1)/11(2)/07, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (लेखा प्रथम) ओबराय मोटर्स माजरा, देहरादून।
- 2- आयुक्त गढ़वाल/कुमायू मंडल, पीडी/नैनीताल।
- 3- समस्त जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 4- मुख्य अभियन्ता, गढ़वाल/कुमायू क्षेत्र, लो०नि०वि०, पीडी/अल्मोड़ा।
- 5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
- 6- वित्त अनुभाग-2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ उत्तराखण्ड शासन।
- 7- बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय उत्तराखण्ड शासन।
- 8- निदेशक राष्ट्रीय सूचना केन्द्र उत्तराखण्ड देहरादून।
- 9- लोक निर्माण अनुभाग-1/3 उत्तराखण्ड शासन।
- 10- गार्ड बुक।

आज्ञा से,
प्रदीप सिंह रावत
(प्रदीप सिंह रावत)
उप सचिव।